Home to accommodate Aged, Infirm, Ailing and Physically-handicapped Freedom Fighters

8456 SHRI M D. JAMILURRAHMAN Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) if and when the Home and/or Health Ministry approached his Ministry for sparing a building for a Home to accommodate the Aged, Infirm, Ailing and Physically-handicapped Freedom fighters, and

(b) action so far taken to provide it?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA) (a) and (b) In February, 1974, the Ministry of Home Affairs approached the Directorate of Estates for allotting suitable accommodation for starting a temporary Home for Freedom Fighters Two type V houses at Baird Road were offered, but the Ministry of Home Affairs did not find them suitable They have asked for two other houses The matter is under consideration

कुछ चुनी हुई रूसी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन

8457. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1970 में भारत रूस संयुक्त बोर्ड ने कुछ चुनी हुई रूसी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन करने का निश्चय किया था, और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की पाठ्य सामग्री क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) चुनिन्दा रूसी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अनुवादों के प्रकाशन के लिये रूसी जानने वाले भारतीय विशेषज्ञों तथा रूसी विशेषज्ञों के बीच सहयोग संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड की जून, 1970 में हुई बैठक में विचार किया गया था। तथापि कोई ठोस योजना तैयार नहीं की गई थी,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में भूमि खरीदने तथा मकान बनाने के लिए गरीबों को केन्द्रीय निधि

8458. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1973-74 में मकान बनाने के लिए गरीबों को जमीन खरीदने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार से कुछ रकम की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम की मांग की गई थी और कितनी रकम राज्य सरकार को दी गई ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने कितने जिलों के लिए अलग-अलग रकम की मांग की थी उन जिलों को बहुत कम और जिन जिलों का उल्लेख नही किया गया था उनको बिल्कुल भी नही दी गई, और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस मद पर कई करोड रुपये खर्च कर दिए है जबकि अन्य राज्यों को इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (ग) 1973–74 तक, मध्य प्रदेश सरकार ने 15 00 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता अपनी परियोजनाओ के लिए मागी थी जो, जहा आवश्यक हो, भूमि का अर्जन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे भूमिहीन मजदूरो को आवास-स्थल देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अधीन राज्य म 9,59 000 आवास-स्थलो के विकास के लिए थी ।

प्रारम्भ मे, निम्नलिखित कारणो से राज्य सरकार से प्राप्त किसी भी परियोजना को स्वीकार करना सभव नही हुआ था :—

(i) राज्य सरकार ने उन भूमिहीन मजदूरो को वास भूमि के अधिकार देने के बारे मे कोई कानून नही बनाया था जिन्होने गैर-सरकारी भूमि पर मकान, झुग्गिया बनाई हुई हैं । यह शर्त इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तों मे से एक है ।

(ii) योजना को देश भर मे कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1973–74 में 5 करोड रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी जिसे मितव्ययिता के उपाय के रूप में घटा कर 3.5 करोड रुपये कर दिया गया है । वर्ष 1972–73 मे अनुमोदित परियोजनाओ के सम्बन्ध मे लगभग 12 करोड रुपये की प्रत्याशित अधिनीत वचनबद्धताओं की तुलना मे यह घटाई गई राशि अपर्याप्त समझी गई ।

स्थिति का पुनरीक्षण किया गया तथा यह मालूम हुआ कि पहले स्वीकृत की गई परियोजनाओ के लिए राज्य सरकारो की मागो तथा निधियो की उपलब्धता के अनुसार, कुछ नई परियोजनाए स्वीकृत की जा सकती थी । तदनुसार, भारत सरकार ने 199 63 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 1,34,496 आवास स्थलो के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार की परियोजनाए स्वीकृत की । परियोजनाओ का तत्काल निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार को 49.91 लाख रुपये की राशि दे दी गई ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यय की गई राशि मालूम नही है । स्वीकृत आवास स्थलो की सख्या, उनकी अनुमोदित लागत तथा विभिन्न राज्य सरकारो को, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, योजना के अधीन दी गई निधियों का एक विवरण पत्र सलग्न है ।

31-3-74 तक ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा दी गई निधियों का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत परि-योजनाओं की संख्या	आवास स्थलों की सं०	अनुमोदित लागत	दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
				(लाख रुपयों में)	
1	आन्ध्र प्रदेश	19	79,598	131 13	32 78
2	बिहार	44	32,608	62 87	15 71
3	गुजरात	85	1,62 676	306 58	76 65
4	हरियाणा	1	51	0 08	0 06
5	हिमाचल प्रदेश	7	583	0 87	0.38
6	कर्नाटक	109	1,72,597	239 38	59 84
7	केरल	960 (पचायतें)	96 000	677 76	358 44
8	मध्य प्रदेश	73	1,34,496	199 63	49 91
9	महाराष्ट्र	83	1,08,962	164 56	41 14
10	उड़ीसा	2	3 349	8 40	2 10
11	पंजाब	3	12,082	31 68	16 56
12	राजस्थान	46	17,832	28 76	7 19
13	तमिल नाडु	36	33,692	75 51	56 64
14	उत्तर प्रदेश	27	19,808	30 85	7 71
15	पश्चिमी बंगाल	12	11,166	19 39	4 85
	जोड़	1,507	8,85,502	1977 45	729.96